

SHRI R. P. DAS : When it is provided in the time-table how can it be cancelled on flimsy grounds ? How can you cancel like that causing great inconvenience to the daily travelling passengers ?

SHRI HANUMANTHAIYA : I would only submit that the grounds that I have given are not flimsy and that they are causing the railways to run under such chaotic conditions that it is almost impossible to run the rakes on time. It is the violence that is taking place that is responsible for this.

SHRI P.R. DAS MUNSI : I do not deny the fact that there has been cancellation of trains due to civil disturbances etc. It is a fact and I, agree with my hon. friend on this point. But sometimes, it happens that there is scarcity of rakes; when the passengers are put to inconvenience and they ask the railway authorities for more rakes. The authority say that there is scarcity of rakes. I think that this question has been put for this reason. The Sealdah division and the Sealdah station have the highest density of passengers in Asia. Is the hon. Minister aware that unless the number of trains is increased and special arrangements are made to avoid all these disturbances and alternative trains are run, these problems cannot be solved ? May I know what steps the hon. Minister proposes to take to give relief to the travelling public immediately ?

SHRI HANUMANTHAIYA : I have answered the question already. In fact, the Railway Administration are trying to improve the train services but the difficulties in the way have been enumerated already. I agree with the hon. Member that the train services should be regular.

श्री हुकम चन्द कछवाय : पूर्व रेलवे के अन्दर जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, शायद ही किसी दूसरी रेलवे में होती होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि इन घटनाओं को रोकने के लिए आपने कौन से विशेष कदम उठाये हैं, जिससे कि रेलवे सम्पत्ति को हानि न हो। कुछ यात्री ऐसे काम करते हैं, लेकिन सारे यात्रियों को उसका फल भुगतना पड़ता है। सब यात्रियों

को सहूलियतें मिलें, इस दृष्टि से आप कौन से ठोस कदम उठाने जा रहे हैं ?

SHRI HANUMANTHAIYA : We are taking various steps. The co-operation of the State Government authorities is needed, and we have been having talks with them. We have to increase the protection forces. If necessary, it is under contemplation that the Army may be requisitioned in order to put a stop to all these robberies, train lootings etc. Various steps are being devised from time to time. The hon. Member will see that within the next two or three months, we are going to take very serious steps.

DR. RANEN SEN : The hon Minister should not take shelter behind this plea that there are *bundhs* and strikes and disturbances etc. Is it not a fact that three years back, the Railway Minister had himself admitted that there was shortage of rakes in certain parts of India. Therefore, the question raised here raises a relevant point. As far as we know there is shortage of rakes. Therefore, would the hon. Minister make enquiries from the railway authorities and find out if there is shortage of rakes and if so, see that the shortage is made up ?

SHRI HANUMANTHAIYA : Yes; I agree with the hon. Member. But the information furnished to me from the Sealdah station is that the rakes are available, but the difficulty is one of movement. But I shall make enquiries again in the light of the hon. Member's observation, whether the rakes are available in sufficient number.

MR. SPEAKER : Next question No. 38.

SHRI S. R. DAMANI : May I submit that my question No. 59 on the same subject may also be taken up along with this ?

MR. SPEAKER : Yes. He may also ask his question now.

जीवनीक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में प्राचीन योजनायें

38. जी अटक बिहारो बाकवेची : क्या

औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के कुछ जिलों के लिए अभी हाल में पचास प्रतिशत ग्रामीण योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो पहले मंजूर की गई 55 ग्रामीण औद्योगिक योजनाओं के बारे में बिगत अनुभव का व्योरा क्या है और अभी हाल में मंजूर योजनाओं द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के असंतुलन को किस सीमा तक समाप्त किये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). इस समय केवल 54 ग्रामीण उद्योग योजनाएं हैं। ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम प्रारम्भ में 49 चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 1962-63 की अवधि में शुरू किया गया था। इसके परिणाम उत्साहवर्द्धक रहे हैं। चालू वर्ष में पांच नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं—इनमें से एक हरियाणा में तथा अन्य चार आंध्र प्रदेश के करीमनगर, गुजरात के जूनागढ़, मंसूर के बेलगांव, तथा उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिलों के ग्रामीण विद्युत सहकारी परियोजना क्षेत्रों में हैं। मार्च, 1970 के अन्त तक लगभग 29,000 औद्योगिक एकक चल रहे थे जिनमें से लगभग 13,000 नए एकक थे। इस पर अनुमानतः कुल 13.46 करोड़ रुपये का विनियोजन किया गया था और 1969-70 में 10 करोड़ रुपये के मूल्य का उत्पादन हुआ। इससे लगभग 1,15,000 लोगों को रोजगार मिला। फिर भी, सभी परियोजना क्षेत्रों में प्रगति एक जैसी नहीं रही और जिन क्षेत्रों में प्रगति संतोषजनक नहीं रही उनमें समय-समय पर सुधार करने के लिए उपाय किये गये हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री जी ने कहा कि 1962 में जो परियोजनाएँ चालू की गई थी उनके परिणाम उत्साहवर्द्धक रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा क्या कोई मंत्रालय में ऐसी व्यवस्था है कि इन परियोजनाओं का समय-समय पर मूल्यांकन किया जा सके और क्या सदन को उन मूल्यांकनों से अवगत कराया जायेगा ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : योजना आयोग ऐसी परियोजनाओं का समय-समय मूल्यांकन करता रहा है। जिन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ये योजनाएँ चालू हैं उनका भी मूल्यांकन किया गया था और उससे पता चला है कि कुछ योजनाओं की स्थिति काफी अच्छी है, कुछ की स्थिति मध्यम है और कुछ की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जिन योजनाओं के बारे में ऐसा बताया गया कि उनकी स्थिति संतोषजनक नहीं है उनमें सुधार लाने के लिए सरकार ने आवश्यक कार्यवाही की है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या मंत्री महोदय यह स्वीकार करते हैं कि इन योजनाओं के लिए जो धनराशि रखी गई है वह अपर्याप्त है और ग्रामीण क्षेत्रों में यदि बेकारी का निराकरण करना है तो बड़े पैमाने पर धरेक उद्योग-धंधों का विकास करना होगा ? मैं जानना चाहूँगा कि बेकारी के निराकरण के लिए जो बजट में 55 करोड़ रुपये रखा गया है क्या उसमें से कोई धनराशि इन योजनाओं पर भी खर्च की जायेगी या योजना आयोग इस प्रकार की योजनाओं के विस्तार के लिए अलग से धनराशि का प्राविधान करने जा रहा है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जहाँ तक 55 करोड़ की धनराशि का सवाल है, वह बिल्कुल अलग मामला है उसके सम्बन्ध में अभी विचार हो रहा है। लेकिन जहाँ तक इन योजनाओं का सवाल है, वैसे मैंने अपने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया कि हमने अब तक कुल मिलाकर 54

योजनाएँ ली हैं। पांचवीं आयोजना के अन्तर्गत 50 और नयी योजनाएँ ली जा सकें, इसके लिए छान-बीन चल रही है। इसके बारे में जब छान-बीन पूरी हो जायेगी तब अन्तिम रूप से फैसला लिया जायेगा। जहाँ तक धनराशि का सवाल है, इन योजनाओं को धनराशि की वजह से कार्यान्वित करने में अभी तक कोई ऐसी खास कठिनाई नहीं मालूम पड़ी है।

Policy for Industrialisation of Backward Areas

*69. SHRI S. R. DAMANI : Will the MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (AUDYOGIK VIKAS MANTRI) be pleased to state :

(a) the progress made to implement the policy of industrialising areas indentified as backward or under developed;

(b) whether any schemes have been formulated specially for this purpose and if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor and how are the promises made to the backward areas going to be fulfilled ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (AUDYOGIK VIKAS MANTRALAYA MEN UP MANTRI) (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

(a) to (c). In pursuance of the decisions of the N.D.C. Committee on the recommendations of the Working Groups on Criteria and Incentives for promotion of industries in backward areas, certain industrially backward districts have recently been selected to qualify for concessional finance from the financial institutions. Besides, certain districts/areas have also been selected to qualify for 10% outright grant or subsidy by the Centre to industries on their fixed capital investment. Also, Government are considering a recommendation of the Planning Commission to give transport subsidy equivalent to 50% of the

transport cost of both raw material and finished products for all new industrial units to be set up in the States of Jammu & Kashmir and Assam including Meghalaya, Nagaland and Union Territories of Manipur, Tripura and N.E.F.A.. The transport subsidy will also be available to existing units for expansion or diversification if this leads to an increase in production of at least 25% over the average annual output during the preceding three years.

Administrative details of the scheme of 10% Central grant and transport subsidy and the procedure for their disbursement are being worked out.

SHRI S. R. DAMANI : According to the statement, Government have selected certain backward districts/areas for concessional financial assistance for setting up industries. The matter is under consideration. How long will it take to come to a final decision on the recommendation of the NDC and the Planning Commission ? Also, which are the districts declared as backward ?

SHRI SIDDHESHWAR PRASAD : The districts which are now under this programme include those in Andhra Pradesh, Assam etc. It is a long statement. I will lay it on the Table of the House.

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : मैं जानना चाहता हूँ क्या मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश के पर्वती जिलों को भी इस लिस्ट में इनकलूड करने की कृपा करेंगे ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : यह जो क्षेत्र जिनको हम इन योजनाओं के अन्तर्गत लाते हैं उनके सम्बन्ध में राज्य सरकारों से सुझाव मागते हैं। यदि राज्य सरकारें पहाड़ी जिलों के सम्बन्ध में भी सुझाव देंगी तो हम उन पर भी सहानुभूति के साथ विचार करेंगे।

श्री आर० बी० बड़े : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि कूक जिल्ला प्रदेश को भी बैकवर्ड रीजन सम्झा जाता है इसलिए क्या